

'अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव जीत के आइये' एलजी सक्सेना पर भड़के दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी सक्सेना पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि रोज बाबुओं की तरह चिट्ठी लिखने से आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। संविधान को पढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि चुनी हुई सरकार के मामले में चुने हुए मंत्री को LG आदेश देंगे। पानी स्वास्थ्यट्रांसपोर्ट फारेस्ट सभी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं। LG के अधीन नहीं आते।



परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी सक्सेना पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि रोज बाबुओं की तरह चिट्ठी लिखने से आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। संविधान को पढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि चुनी हुई सरकार के मामले में चुने हुए मंत्री को LG आदेश देंगे। पानी स्वास्थ्यट्रांसपोर्ट फारेस्ट सभी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं। LG के अधीन नहीं आते।

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी वीके सक्सेना को

जमकर खरीखोटी सुनाई है। दरअसल, एलजी ने मंत्रियों के बैठक में न आने को लेकर गृह मंत्रालय से चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। भारद्वाज ने कहा कि LG सब को सरकार चलाने का शौक चढ़ा है तो अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़िए। जीत के आइये। मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता का दिल जीतना पड़ता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रोज बाबुओं की तरह चिट्ठी लिखने से आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। संविधान को पढ़िए। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि चुनी हुई सरकार के मामले में चुने हुए मंत्री को LG आदेश देंगे। पानी, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट,

फारेस्ट सभी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं। LG के अधीन नहीं आते। आचार संहिता की बात कहकर नहीं आएंगे मंत्री: एलजी बता दें, उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक में उनके मंत्री नहीं पहुंचे। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि मंत्रियों की एक बैठक बुलाई, ताकि दिल्ली के रोजमर्रा के काम प्रभावित न हो। लेकिन मंत्रियों ने यह कहकर आने से मना कर दिया कि अभी आचार संहिता लागू है।

'चुप नहीं बैठेंगे, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव पर दर्ज होगा केस', दवाईयों की कमी पर सौरभ भारद्वाज

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर दवाओं की कमी के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है या गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो क्या अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा शुरू नहीं किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे मैं इसके लिए मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कराऊंगा।

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों और औषधालयों में दवाओं की कमी को लेकर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों और औषधालयों में दवाओं की कमी और कुछ संबंधित अधिकारियों द्वारा मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त नैदानिक परीक्षणों को रोकने का मुद्दा आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने नियम 54 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया।

सौरभ भारद्वाज ने सदन में दोरिपोर्ट पेश की

भारद्वाज ने इसके जवाब में सदन में दोरिपोर्ट पेश की, जिनमें मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव की रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें कहा

गया है कि उन्होंने लिखित रूप में दिया है कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में दवाएं उपलब्ध थीं और जो अनुपलब्ध थीं, उन्हें पूरा कर दिया गया है।

मंत्री ने कहा कि दूसरी रिपोर्ट विधायकों की प्रतिक्रिया, समाचार रिपोर्ट और उनकी अपनी पूछताछ पर आधारित थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत बोलियां उपलब्ध होने के बावजूद 2023 की केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया। उन्होंने कहा सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और मोहल्ला क्लीनिकों के लिए दवाएं सीपीए के माध्यम से खरीदी जाती हैं।

पत्र लिखने के बाद कोई कार्रवाई नहीं: भारद्वाज

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनवरी में दवा की कमी और मोहल्ला क्लीनिक में जांच बंद होने का मामला सामने आया था। उन्होंने विवरण और कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को 12 फरवरी और फिर चार मार्च और 18 मार्च को लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अस्पतालों द्वारा स्थानीय खरीद या अनुबंध दर पर खरीद के माध्यम से दवा खरीद के वैकल्पिक तरीके हैं, लेकिन चिकित्सा अधीक्षकों और चिकित्सा निदेशकों ने एक मार्च और 11 मार्च को हुई बैठकों में बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के कारण यह अ संभव हो गया है।

छठी से लेकर 9वीं में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानिए लास्ट डेट

परिवहन विशेष न्यूज

अधिकारी ने बताया कि पहले दिन बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी जो विद्यार्थी पांचवीं से लेकर सातवीं तक की कक्षा से किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से उत्तीर्ण हैं या जो विद्यार्थी स्कूल से बाहर हैं वो इस प्रक्रिया में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले चरण की ये आवेदन प्रक्रिया 17 अप्रैल तक चलेगी।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नान प्लान दाखिला के तहत छठवीं से लेकर नौवीं तक की कक्षाओं में दाखिले को लेकर आवेदन की प्रक्रिया आठ अप्रैल से शुरू हो गई है। पहले चरण की ये आवेदन प्रक्रिया 17 अप्रैल तक चलेगी।

पहले दिन बड़ी संख्या में मिले आवेदन

शिक्षा निदेशालय के अधिकारी ने बताया कि पहले दिन बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी जो विद्यार्थी पांचवीं से लेकर सातवीं तक की कक्षा से किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से उत्तीर्ण हैं या जो



विद्यार्थी स्कूल से बाहर हैं वो इस प्रक्रिया में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वहीं, नौवीं में केवल वहीं विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी स्कूल से आठवीं उत्तीर्ण की हो। पहले चरण के तहत 29 अप्रैल को विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्कूलों की सूची जारी होगी। 30 अप्रैल को विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्कूलों में दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दूसरे चरण के तहत आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी।

तीसरे चरण की दाखिले की

प्रक्रिया 27 जून को विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्कूलों की सूची जारी होगी और 28 जून से छह जुलाई तक विद्यार्थी ऑनलाइन स्कूलों में पहुंचकर दस्तावेजों का सत्यापन कर सकते हैं। 10 जुलाई से 31 जुलाई तक को तीसरे चरण के तहत विद्यार्थी दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। 12 अगस्त को दाखिले के लिए ऑनलाइन स्कूलों की सूची जारी होगी और 13 अगस्त से 31 अगस्त तक विद्यार्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा।

दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं पर चर्चा की मांग पर अड़े बीजेपी विधायक, हंगामे के बाद मार्शल ने किया बाहर

परिवहन विशेष न्यूज

बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का महिमा मंडन करना बंद करे। दिल्ली की जनता पहले से ही पानी सीवर प्रदूषण और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से घिरी हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जनता की नहीं सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता है।

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित अनियमितताओं पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायकों को सोमवार को मार्शलों ने दिल्ली विधानसभा से बाहर कर दिया। सदन की कार्यवाही सदस्यों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे उठाने के साथ शुरू हुई।

मगर भाजपा विधायक डीजेबी में कथित अनियमितताओं पर चर्चा की मांग करने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने अनुरोध को खारिज कर दिया और विपक्षी सदस्यों को बैठने के लिए कहा। जब भाजपा विधायक अपनी मांग पर अड़े रहे तो गोयल ने मार्शलों से उन्हें सदन से बाहर ले जाने को कहा। बाद में भाजपा के आठ विधायकों ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया।



'जल बोर्ड का पैसा अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च'

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि आप सरकार को खुद की रिपोर्ट कह रही है कि जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपये के घाटे में है और 28,400 करोड़ रुपये का हिसाब कोई नहीं दे सकता। बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि जल बोर्ड को दिया गया पैसा अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया और करोड़ों का नुकसान हुआ, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि लोग निराश और परेशान हैं।

बिधूड़ी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का महिमा मंडन करना बंद करे। दिल्ली की जनता पहले से ही पानी, सीवर, प्रदूषण और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से घिरी हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जनता की नहीं सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता है।

केजरीवाल को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे: बिधूड़ी

उन्होंने कहा कि केजरीवाल को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बिधूड़ी ने कहा कि

आम आदमी पार्टी के नेता बारी-बारी से यह झुगमा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने के बाद समस्याएं गंभीर हो रही हैं और वह जेल में रहते हुए निर्देश जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मंत्री आतिशी ने केजरीवाल का महिमा मंडन करते हुए घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा था कि दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या गंभीर है और केजरीवाल को इसकी चिंता है। अब सौरभ भारद्वाज ने स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों में दवाइयां नहीं मिल रही और मुफ्त टेस्ट नहीं हो रहे।

कंप्यूटर पर एआईएमएल के जरिये कर रहे हैं फिलहाल जांच, भविष्य में देंगे एप का रूप सिर्फ पांच मिनट में मिलेंगे किडनी टेस्ट के रिजल्ट, IIT दिल्ली द्वारा तैयार ऐप से घर बैठे मिलेगा परिणाम

परिवहन विशेष न्यूज

आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग के जरिये एप में इमेज प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद एप बता देगा कि एल्यूमिन और क्रिटिनन की यूरिन में कितनी मात्रा है। प्रयोगशाला में जांच में एक से दो दिन लग जाते हैं। लेकिन इसके जरिये पांच मिनट में परिणाम सामने आ जाएंगे। इस प्रक्रिया में तत्वों की मात्रा की जांच की जाती है। आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग के जरिये एप में इमेज प्रोसेसिंग होगी।

नई दिल्ली। किडनी रोगों का समय रहते पता लगाने की दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली काम कर रहा है। आईआईटीडी के सेंटर फार सेंसेस, इंस्ट्रुमेंटेशन एंड सायबर- फिजिकल सिस्टम इंजीनियरिंग (सेंस) ने ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है, जिसके जरिए यूरिन सैंपल के इस्तेमाल से किडनी में एल्यूमिन और क्रिटिनन की मात्रा का पता लगाया जा सकता है।

इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं और हाल में शोध पत्र भी प्रकाशित हुआ है। आईआईटीडी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के साथ मिलकर प्रोग्राम तैयार कर रहा है। भविष्य में प्रोग्राम को मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में डिजाइन किया जाएगा, जिससे लोग घर बैठे टेस्ट कर सकेंगे।

सेंस में एसोसिएट प्रोफेसर और शोध के प्रमुख प्रो. सतीश कुमार दुबे ने बताया कि प्रोजेक्ट पर



तीन वर्षों से काम चल रहा है। यूरिन की जांच के लिए सैंपल आती हैं, उसको यूरिन सैंपल में डालने के बाद हर पेच का रंग बदल जाता है। हर पेच में कैमिकल होता है। इस सैंपल की फोटो मरीज को लेनी होगी और उसके बाद इसे एप में डालना होगा।

पांच मिनट में परिणाम सामने आ जाएंगे

आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग के जरिये एप में इमेज प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद एप बता देगा कि एल्यूमिन और क्रिटिनन की यूरिन में कितनी मात्रा है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में जांच में एक से दो दिन लग जाते हैं। लेकिन, इसके जरिये पांच मिनट में परिणाम सामने आ जाएंगे। इस प्रक्रिया में तत्वों की मात्रा की जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि सैंपल से सामान्यतौर पर बीमारी का पता चल जाता है। लेकिन, हानिकारक तत्व की मात्रा पता नहीं चलती। उन्होंने कहा कि हर मोबाइल के कैमरे की क्षमता अलग- अलग होती है। फोटो लेते वक्त वहां की रोशनी का उस पर प्रभाव पड़ता है। एप के जरिये हम काम कर रहे हैं कि रोशनी का

प्रभाव जांच पर न पड़े। सैंपल के रंग रोशनी से प्रभावित न हों।

बीमारी को शुरूआत में ही पकड़ने में सहायक

'क्वालिफिकेशन आफ माइक्रोएल्यूमिन्यूरिया यूजिंग स्मार्टफोन- बेस्ड

ईद के दौरान अखूनजी मस्जिद स्थल पर नमाज अदा करने की अनुमति से दिल्ली HC का इनकार

अखूनजी मस्जिद स्थल पर रमजान के महीने और ईद के दौरान नमाज अदा करने की अनुमति देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया। इस दौरान एकल पीठ के निर्णय पर अपील दायर करने में देरी पर अदालत ने सवाल उठाया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर एक घंटे के लिए ईद की नमाज की अनुमति दी जाती है तो स्वर्ग नहीं गिर जाएगा।

नई दिल्ली। ग़रीबों में ध्वस्त अखूनजी मस्जिद पर रमजान के महीने और ईद के दौरान नमाज अदा करने की अनुमति देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नमगीत व न्यायाधीश नमगीत सिंह अरोड़ा की पीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि एकल पीठ का आदेश 11 मार्च का है और अब आठ अप्रैल का चुकी है, आदिश अपील दायर करने में इतना इंतजार क्यों किया गया।

7 मई को होगी सुनवाई : अदालत ने कहा कि इस पर उस अपील के साथ सात मई को सुनवाई होगी। कोई अंतरिम आदेश नहीं ले सकता। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता संगठन की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि संभित पिछले दराजों से प्रवेश पाने की कोशिश नहीं कर रही है।

बाबरी मस्जिद मामले और जानवापी मामले पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक अदालतों ने पहले धार्मिक गान्ध्याताओं का सम्मान किया है और धार्मिक स्थलों के संबंध में कानूनी विवादों के लंबित रखे तक प्राथम्यता करने की अनुमति दी है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर एक घंटे के लिए ईद की नमाज की अनुमति दी जाती है, तो स्वर्ग नहीं गिर जाएगा। याचिकाकर्ता ने दिया तर्क : उन्होंने कहा कि भारत के लोगों, विशेष रूप से मुसलमानों को एक संदेश जाना कि अदालतें मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए समान रूप से उत्साहित हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि सात मई तक रमजान और ईद की अवधि समाप्त हो जायेगी। सलाह, अदालत ने मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। 111 मार्च को एकल न्यायाधीश ने अखूनजी मस्जिद में रमजान माह में नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

प्वाइंट आफ केयर डिवाइस फार अलॉ डिग्नोसिस आफ क्रॉनिक किडनी डिस्ीज' प्रोजेक्ट पर प्रोफेसर दुबे के साथ काम कर रही शोध छात्रा सुनीता ने बताया कि हमारे ऐप से एल्यूमिन की मात्रा 7.5 ग्राम तक मापी जा सकती है। इससे बीमारी के शुरुआती चरण में ही उसका पता लगाया जा सकता है।

लैब में इतनी कम मात्रा को मापना मुश्किल है। इससे समय रहते उपचार शुरू किया जा सकता है। किडनी की बीमारी में लक्षण दिखने के बाद ही इसका पता चल पाता है। अगर हानिकारक तत्वों का यूरिन में शुरुआती स्तर पर ही पता चल जाए तो इसे समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है।

एम्स की कैथ लैब से जांच के लिए ले रहे सैंपल

प्रो. दुबे ने कहा कि एम्स की कैथ लैब से हम जांच के लिए सैंपल ले रहे हैं। जांच में उनकी मदद भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी योजना सुदूर इलाकों में राहत पहुंचाने की है। जहां जांच के साधन सुलभ नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने काफी समय लगता है।

वहां यूरिन सैंपल मुहैया करा दी जाए, तो जांच आसानी से की जा सकती है। सैंपल छह से सात रुपये में आ जाती है। इसलिए घर पर भी इससे जांच कर सकते हैं। हाल में इसका शोध पत्र आईईईई सेंसेस जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

लापता

नाम : संजना पुत्री श्री अजय कुमार आयु :13 वर्ष लिंग : महिला ऊंचाई : 5 '1" शरीर : पतला बाल :*काले आँखें :*काली अंतिम बार देखा गया : गली नंबर 10 संजय कॉलोनी नरेला दिल्ली - 110040 अंतिम बार देखे की की तिथि : 07/04/2024 (समय : 6 :30 बजे) वस्त्र : हरे रंग की प्रिंटेड कुर्ती और जींस और काले रंग के फुटवियर संपर्क जानकारी : यदि आपके पास लापता व्यक्ति के टिकाने के बारे में कोई जानकारी है, तो कृपया संपर्क करें : अजय कुमार पुत्र श्री . ईश्वर सिंह निवासी नं.22/2, गली नं.10, संजय कॉलोनी, नरेला, दिल्ली - 110040, मोबाइल नं. +91-9250929732 . पुलिस स्टेशन : नरेला, दिल्ली



नोएडा की बेटी अंशिका सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में लहराया भारत का परचम, 2 साल में खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी

नोएडा की बेटी अंशिका सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में देश का परचम लहराया है। 2022 में खुद के दम पर आउट-रीड एप के नाम से स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत करके 2 साल में करोड़ों की कंपनी स्थापित कर दी। अंशिका लक्ष्य अगले पांच वर्ष में इस कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। वह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी संतोष कुमार की बड़ी बेटी हैं।

ग्रेटर नोएडा। कहते हैं कि मन में यदि चाह हो तो सफलता खुद-बखुद कदम चूमती है। नोएडा के सेक्टर 14ए की रहने वाली बेटी अंशिका सिंह ने इस कथन को साकार कर दिखाया है। 2022 में एक अनूठा एप बनाकर स्टार्टअप के रूप में इसे शुरू किया। दो साल से भी कम समय में उस कंपनी की हैसियत 27 करोड़ रुपये हो चुकी है।

आस्ट्रेलियाई सरकार ने किया सम्मानित

इस स्टार्टअप के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अंशिका को सम्मानित भी किया। दरअसल, अंशिका सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी संतोष कुमार की बड़ी बेटी हैं। उनका परिवार मूल रूप से हाथरस से है। अंशिका ने 12वीं तक की पढ़ाई डीपीएस नोएडा से पूरी करने के बाद 2017 में रायल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्कॉलरशिप के साथ स्नातक की पढ़ाई की।

2022 में शुरू की थी स्टार्टअप कंपनी

इसके बाद 2022 में खुद के दम पर आउट-रीड एप के नाम से स्टार्टअप



कंपनी की नींव रखी। इस ऐप से किसी भी बड़े दस्तावेज का सारांश चंद पलों में प्राप्त कर सकते हैं। आपको हजारों पन्ने का डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सभी जरूरी बातें चंद लाइनों में सिमटकर आ जाएंगी। किसी भी रिसर्च डॉक्यूमेंट का सारांश इस एप की मदद से प्राप्त किया जा सकता है।

इसका इस्तेमाल शिक्षण संस्थाओं, रिसर्च सेंटरों, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने समेत तमाम जगहों पर किया जा सकता है। इसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप में से एक चुना गया, जिसके लिए साउथ ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अंशिका को पुरस्कृत भी किया। वे अभी मेलबर्न में रह रही हैं। गुगल के मुख्य वैज्ञानिक जेफ डीन, यूएस कंपनी टेक स्टार ने शुरुआती निवेश के लिए सहयोग किया है।

2500 करोड़ की कंपनी बनाने का लक्ष्य

अंशिका कहती हैं कि पढ़ाई के दौरान ही उनके दिमाग में यह आइडिया आया। इस पर काम शुरू किया और दो साल की कड़ी मेहनत के बाद अपनी सहपाठी गाजियाबाद की जान्ही चौधरी के साथ मिलकर एप को तैयार किया। उनका लक्ष्य अगले पांच वर्ष में इस कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाना है।

जब भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बोले, प्रमुख सचिव गृह से बात कराऊं क्या?

परिवहन विशेष न्यूज

खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में कमल का निशान लेकर हाथ हिला रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतुल गर्ग और सांसद वीके सिंह के हाथ में कमल का निशान था। जैसे ही रोड शो समाप्ति स्थल चौधरी मोड पर पहुंचा तो करीब तीन घंटे से इंतजार में खड़े समर्थकों में उत्साह देखने लायक था। उन्होंने मोदी-मोदी अबकी बार 400 पार के नारे लगाए।

गाजियाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान पुलिस अधिकारियों की भाजपा नेताओं से कई बार नोकझोंक हुई। मालीवाड़ा चौक पर बने रोड शो रुट के पहले सेक्टर में भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह पहुंचे तो एसीपी नितिन सिंह ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, दूसरे सेक्टर का ग़िल खोल वहां मौजूद समर्थकों को पहले सेक्टर में प्रवेश दे दिया।

परिचय देने के बाद भी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता को पहले सेक्टर में अंदर नहीं आने दिया तो वह गुस्सा गए। गुस्से में लाल होकर भाजपा के प्रदेश एसएन सिंह एसीपी नितिन सिंह से बोले, कौन पुलिस अधिकारी है तो हमें अंदर नहीं आने दे रहा है। प्रमुख सचिव गृह से बात कराऊं क्या...?

भाजपा नेता की पुलिसकर्मीयों से हुई तीखी नोकझोंक

इसके बाद उन्हें पहले सेक्टर में प्रवेश करने दिया गया है। इसी तरह का वाक्या भाजपा नेता प्रदीप चौहान के साथ हुआ। उनकी भी प्रवेश करने के दौरान पुलिसकर्मीयों से तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा नेता राजीव शर्मा ने दोनों पक्षों को समझाकर



गुरुग्राम शहर के कई क्षेत्रों में 36 घंटे बंद रहेगी पानी की सप्लाई

गुरुग्राम शहर में इन दिनों गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल खपत भी बढ़ गई। इस वीह शहर के कई क्षेत्रों में सोमवार को सुबह दस बजे से नौ अप्रैल को रात दस बजे तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बसई और सेक्टर 16 बूरिस्टिंग स्टेशन गुरुग्राम से घरों में पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी। गर्मी के दिनों में 36 घंटे पेयजल आपूर्ति बंद होने से पानी का संकट बढ़ सकता है।

गुरुग्राम। शहर के कई क्षेत्रों में 36 घंटे पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी। बसई चौक से हीरो हॉंडा चौक तक बरसाती नाले का निर्माण कार्य

करने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा सोमवार को सुबह दस बजे से नौ अप्रैल को रात दस बजे तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बसई और सेक्टर 16 बूरिस्टिंग स्टेशन गुरुग्राम से घरों में पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी।

इन इलाकों में बंद रहेगी पेयजल आपूर्ति शेटाउन अवधि के दौरान गांव बसई, कादीपुर, सिरहौल, चक्रपुर, नाथूपुर, सिकंदरपुर, डूंडाहड़ा, सुखराली, गोशाला बूस्टर, सेक्टर 37 और 34, सिविल लाईंस, हंस एंकेलवर, सेक्टर 10ए, सेक्टर 14, सेक्टर 16,17 18, सेक्टर 15 पार्ट एक और दो, सेक्टर 27,28,29, सेक्टर 30,31 और 32 में पेयजल आपूर्ति बाधित

मामला शांत कराया।

एएसपी व जिला सूचना अधिकारी के बीच हुई नोकझोंक : रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले सुरक्षा में तैनात एएसपी जितेंद्र सिंह व जिला सूचना अधिकारी योगेन्द्र प्रताप सिंह के बीच नोकझोंक हुई।

दरअसल, पुलिस अधिकारी मीडियाकर्मीयों समेत भाजपा नेताओं को सेक्टर में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। इस पर मीडियाकर्मीयों व भाजपा नेताओं ने जिला सूचना अधिकारी योगेन्द्र प्रताप सिंह से शिकायत की।

एएसपी जितेंद्र सिंह से बात की तो वह उनसे भी भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच करीब 10 मिनट तक तीखी नोकझोंक हुई। डीसीपी ग्रामीण विवेक यादव ने मामला शांत कराया।

गर्मी में बढ़ी पेयजल खपत शहर में इन दिनों गर्मी की शुरुआत के साथ ही पेयजल खपत भी बढ़ गई। चंदू बुढ़ेड़ा और बसई प्लांट की क्षमता 570 एमएलडी है और शहर में पानी की मांग 550 एमएलडी से ऊपर पहुंच गई है। 36 घंटे पेयजल आपूर्ति बंद होने से पानी का संकट बढ़ सकता है।

रहेगी। इसके अलावा सेक्टर 38, 39, 40, 41 और 43, सेक्टर 45, 46 (आंशिक), डीएलएफ फेज एक से चार, साइबर सिटी तथा उद्योग विहार फेज एक और दो के अलावा साउथ सिटी-वन, सुशांत लोक-वन और एमजी रोड क्षेत्र में पानी नहीं आएगा।

इसके अलावा सेक्टर 38, 39, 40, 41 और 43, सेक्टर 45, 46 (आंशिक), डीएलएफ फेज एक से चार, साइबर सिटी तथा उद्योग विहार फेज एक और दो के अलावा साउथ सिटी-वन, सुशांत लोक-वन और एमजी रोड क्षेत्र में पानी नहीं आएगा।

इसके अलावा सेक्टर 38, 39, 40, 41 और 43, सेक्टर 45, 46 (आंशिक), डीएलएफ फेज एक से चार, साइबर सिटी तथा उद्योग विहार फेज एक और दो के अलावा साउथ सिटी-वन, सुशांत लोक-वन और एमजी रोड क्षेत्र में पानी नहीं आएगा।

इसके अलावा सेक्टर 38, 39, 40, 41 और 43, सेक्टर 45, 46 (आंशिक), डीएलएफ फेज एक से चार, साइबर सिटी तथा उद्योग विहार फेज एक और दो के अलावा साउथ सिटी-वन, सुशांत लोक-वन और एमजी रोड क्षेत्र में पानी नहीं आएगा।

इसके अलावा सेक्टर 38, 39, 40, 41 और 43, सेक्टर 45, 46 (आंशिक), डीएलएफ फेज एक से चार, साइबर सिटी तथा उद्योग विहार फेज एक और दो के अलावा साउथ सिटी-वन, सुशांत लोक-वन और एमजी रोड क्षेत्र में पानी नहीं आएगा।

10-10 हजार में बेचते थे तमंचा, अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़; इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा में पैकेजिंग फैक्ट्री की आड़ में चल रही तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आशंका है कि लोकसभा चुनाव के दौरान तमंचे अलग-अलग जिलों में सप्लाई किए जाने थे। आरोपितों के कब्जे से बरामद पिस्टल की कीमत 15 लाख रुपये है। आरोपितों ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया है कि वह तमंचा के साथ-साथ पिस्टल भी बनाते थे।

ग्रेटर नोएडा। इकोटेक तीन कोतवाली पुलिस ने पैकेजिंग फैक्ट्री की आड़ में चल रही तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सरगना समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों के कब्जे से 111 अधबनेतमंचे, नौतमंचा, पिस्टलसमेत कई अन्यसामान बरामद हुआ है। चारों आरोपित गाजियाबाद के मोरटा औद्योगिक क्षेत्र में तमंचा बनाने की फैक्ट्री संचालित कर रहे थे।आरोपितोनैलियोपार्टईइंडियाइंडस्ट्रीजलिमिटेडके नामसेफैक्ट्रीखोली थी।इसफैक्ट्रीकी आड़मेंतमंचा फैक्ट्री चल रही थी। पकड़े गए आरोपितों की पहचान शाहफहद, बादल कुमार, शिवमपाल और सादिक के रूपमेंहुई है।

शाहफहद है गिरोह का सरगना शाहफहदगिरोह के सरगना है।पिछलेवर्ष2023 में भीएसटीएफनेउसको अवैधहथियारों केसाथगिरफ्तार किया था। शाहफहद ने वर्ष 2011 में इंजीनियरिंग डिप्लोमा की पढ़ाई की थी। डीसीपी सेंट्रल नोएडा सुनौति ने बताया कि खेड़ा चौगानपुर गोलचक्कर के समीप ब्रेजा

गाजियाबाद में घर से बाहर निकलने पर अपराधियों से अधिक आवा़ा कुत्तों से डर लगने लगा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में पता चला है कि शनिवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक सबसे अधिक लोगों को आवा़ा कुत्ते काट रहे हैं। सोमवार को 24 घंटे में आवा़ा और पालतू कुत्तों ने 85 बच्चों समेत 297 लोगों को काटा है।



बढ़ा तापमान, लगातार दूसरे दिन तेज धूप ने तपाया, जानें आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम

गाजियाबाद में दूसरे दिन सोमवार को तेज धूप की वजह से दोपहर में काफी गर्मी महसूस हुई। हालांकि न्यूनतम तापमान स्थिर रहा। अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन आसमान में हल्के बादल मंडराते रहेंगे। तापमान में एक-दो बढ़ोतरी होने के आसार हैं। वातावरण में आर्द्रता 16 प्रतिशत दर्ज की गई।

गाजियाबाद। दूसरे दिन सोमवार को तेज धूप की वजह से दोपहर में काफी गर्मी महसूस हुई। हालांकि न्यूनतम तापमान स्थिर रहा। अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन आसमान में हल्के बादल मंडराते रहेंगे। तापमान में एक-दो बढ़ोतरी होने के आसार हैं।

लगातार दो दिन से सुबह सवेरे से ही तेज धूप रहती है। सोमवार को दूसरे दिन भी दोपहर में काफी गर्मी महसूस हुई। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा अधिकतम 19 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चली। वातावरण में आर्द्रता 16 प्रतिशत दर्ज की गई।

आसमान में हल्के बादल मंडराते रहे मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को आसमान में हल्के बादल मंडराते रह सकते हैं। तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हवा अधिकतम 14 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगी। वातावरण में आर्द्रता 15 प्रतिशत रहने का अनुमान है।



ललित गर्ग

देश में लंबे समय से चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही है लेकिन चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि दलबदल का बढ़ता दौर कैसे रुके। राजनीति एवं राजनेताओं में नीति एवं सिद्धान्तों की बात प्रमुख होनी चाहिए लेकिन ऐसा न होना लोकतंत्र की बड़ी विसंगति है।

कांग्रेस में लगातार वफादार नेताओं का पलायन जारी है, नये नामों में कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ, महाराष्ट्र के जिम्मेदार एवं पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा, निशाना साधने वाले मुक्तेशबाज विजेंदर, आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जिन्होंने कांग्रेस को बाय-बाय कर दी है। इन सभी ने कांग्रेस के मुद्देविहीन होने, मोदी के विकसित भारत के एजेंडे, राहुल गांधी की अपरिपक्व राजनीति एवं कांग्रेस की सनातन-विरोधी होने को पार्टी से पलायन का कारण बताया है। कुछ भी कहे, यह राजनीति में अवसरवाद का उदाहरण है, इस तरह का बढ़ता दौर चिंताजनक है। भारत की राजनीति में दलबदल की विसंगति देखने विडम्बना आजादी के बाद से लगातार एवं को मिलती रही है। पिछले साढ़े सात दशक के भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक पराभव के अक्स गाढ़े-बगाहे उजागर होते रहे हैं। दलबदल के बढ़ते दौर ने अनेक सवाल खड़े किये हैं। कल तक विपक्ष में जो नेता दागी होते थे,

●●●●●

सतारूढ़ दल में शामिल होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनके दाग दाग नहीं रहते। राजनीति में निष्ठाएं बदलने की स्थितियां आम नागरिकों को उद्बेलित कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि दागी नेता सत्ता की धारा में डुबकी लगाकर दूध का धुला घोषित हो जाता है। हर बार चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में 'आयाराम-गयाaram' का खेल शुरू हो जाता है। विभिन्न दलों के प्रभावी नेताओं को अपने दल में शामिल कराने की होड़ मची है, कभी कोई एक दल बाजी मारती है तो कभी कोई दूसरा दल। सभी सैलिब्रिटी आखिर सत्ता की तरफ ही क्यों भागते हैं? पूर्व न्यायाधीश हो, पूर्व अधिकारी हो, अभिनेता हो या खिलाड़ी राजनीति में अपना भविष्य आजमाते रहे हैं। अगर भाजपा की विचारधारा किसी विजेंदर, गौरव या अनिल शर्मा जैसे लोगों हो क्यों अच्छी लगती है तो सवाल यह भी है कि पिछले पांच साल तक वे कांग्रेस में क्यों रहे? ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो पांच वर्ष के अंत में हुए विधानसभा चुनावों में एक पार्टी के चुनाव विघ्न पर उम्मीदवार थे तो अब दूसरी पार्टी का चुनाव विघ्न लेकर मैदान में उतरते दिख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन्दिनों भाजपा में जो विभिन्न दलों के तीसरे के लगभग राजनेता शामिल हुए हैं उनमें कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना, टीएमसी, टीडीपी, एसपी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता शामिल हैं। क्या यह भाजपा के निश्चित जीत की संभावनाओं का परिणाम है या केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के डर का परिणाम है। निश्चित ही यह स्थिति किसी लोकतंत्र के स्वास्थ्य

●●●●●



के लिये शुभ नहीं कही जा सकती। देश में लंबे समय से चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही है लेकिन चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि दलबदल का बढ़ता दौर कैसे रुके। राजनीति एवं राजनेताओं में नीति एवं सिद्धान्तों की बात प्रमुख होनी चाहिए लेकिन ऐसा न होना लोकतंत्र की बड़ी विसंगति है। राजनीति में सबकुछ जायज है वाली सोच एवं स्वार्थ की नीति दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव का समय हर राजनेता के लिये अपने हित एवं स्वार्थ को चुनने का समय होता है, लेकिन उनके सामने लोकतंत्र के हिताहित का प्रश्न बहुत गौण हो जाता है। चुनावों में आचार संहिता के चलते कई प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, लेकिन राजनीति में में दल-बदल पर नियंत्रण का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है, जबकि यह लोकतंत्र की जीवंतता एवं पवित्रता के लिये प्राथमिकता होनी चाहिए। सत्ता का स्वाद ही ऐसा होता है कि कोई भी राजनेता इससे अछूता नहीं

●●●●●



रहता। इसीलिए आजकल दल बदलने का दौर खूब हो रहा है। यह बात दूसरी है कि ज्यादातर नेताओं में भाजपा का दामन थामने की होड़ मची है। एक दिन पहले भाजपा का दामन थामने एवं जीभर कर कोसने वाले नेताओं को एकाएक भाजपा इतनी अच्छी क्यों लगने लगती है? भाजपा को भी सोचना चाहिए कि आखिर ये अवसरवादी नेता जबभी उनके अनुकूल नहीं हुआ तो उसे भी बाय-बाय कर देंगे? भाजपा को यह भी देखना चाहिए कि पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर चंद घंटों पहले पार्टी में शामिल होने वाले को टिकट देना कहां तक उचित है। दलों को विचार करना ही होगा कि राजनीति के मायने चुनाव जीतना भर ही है या फिर वे विचारधारा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देकर राजनीति को स्वस्थ रखना चाहते हैं। लोकतंत्र में जनता की आवाज की ठेकेदारी राजनैतिक दलों एवं नेताओं ने ले रखी है, पर

●●●●●

इमानदारी से यह दायित्व कोई भी दल एवं नेता सही रूप में नहीं निभा रहा है। "सारे ही दल एवं नेता एक जैसे हैं" यह सुगबुगाहट जनता के बीच बिना कारण लगाए भी स्पष्ट सुनाई देती है। राजनीतिज्ञ पारे की तरह हैं, अगर हम उस पर अँगुली संकेतें तो हमें ही जोशिश करेंगे तो उसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा। सभी दल राजनीति नहीं, स्वार्थ नीति चला रहे हैं। भाजपा को अपने 400 पार के लक्ष्य को हासिल करना है, इसके लिये वह हर-तरह के समझौते कर रही है, दागी नेताओं को भी अपनी पार्टी में जगह दे रही है। ऐसे नेताओं के

अपराधों पर भी परदा डाला जा रहा है। विडंबना है कि राजनीतिक निष्ठा बदलना इन नेताओं के लिये राहतकारी साबित हुआ है। वजह यह कि इन नेताओं से जुड़े अपराध के मामले ठंडे बस्ते में डाल दिये गए हैं। जबकि दलील यह दी जाती है कि मामले बंद नहीं हुए हैं, जरूरत पड़ी तो जांच और कार्रवाई भी होगी। जो विपक्ष के उन आरोपों की पुष्टि करते हैं कि यह कार्रवाई राजनीतिक दुराग्रह एवं आग्रह के रूप में की जाती रही है। यही वजह है कि दल बदलने का फैसला राहत का रास्ता मान लिया जाता है। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अचानक जांच एजेंसियां निष्क्रिय क्यों हो जाती हैं? क्यों किसी एजेंसी को लेकर अदालत को कहना पड़ता है कि फलों एजेंसी पिंजरे में बंद तोता है और मालिक की बोली बोलता है। विपक्ष के ऐसे तमाम आरोपों की ताकिकता हाल में आई एक रिपोर्ट दशाती है।

●●●●●

जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2014 के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेताओं को सतारूढ़ दल में शामिल होने के बाद उनमें से 23 को राहत मिल गई है। इनमें से तीन मामले बंद हो गए हैं और बीस की जांच रुकी हुई है। ऐसे अवसरवादी नेता फिर किसी नई पार्टी में नहीं जाएंगे इसको क्या गारंटी है? अच्छे लोग राजनीति में यदि सिर्फ पद पाने के लिए ही आए तो उसे क्या माना जाए? ऐसी जानी-मानी हस्तियां भी हैं जो आज यहां और कल वहां के उदाहरण पेश कर चुकी हैं। ऐसी सलेब्रिटी को पार्टी में शामिल होते ही टिकट से पुरस्कृत कर दिया जाता है। राजनीतिक दलों को इस बड़ी विसंगति एवं अवसरवादिता पर विचार तो करना ही चाहिए कि आखिर कौन, किस इरादे से पार्टी में आ रहा है। ऐसे डेरों उदाहरण मौजूद हैं कि नामी-गिरामी लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया, टिकट भी मिला और चुनाव जीते भी। उसके बाद जनता से जुड़ ही नहीं पाए और अगले चुनाव में इनका टिकट कट गया। स्वस्थ राजनीति में ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो निष्पक्ष हो, इमानदार हो, सक्षम हो, सुदृढ़ हो, स्पष्ट एवं सर्वजनहिताय का लक्ष्य लेकर चलने वाला हो। लेकिन स्वार्थी, अक्षम, दागी नेताओं को किसी भी दल में जगह देा वह उस दल की मजबूती एवं स्वस्थ राजनीति पर एक बदनुमा दाग है। विडम्बना है कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, मस्तिष्क नहीं। इसका खामियाजा हमारा लोकतंत्र भुगतता है, भुगतता रहा है। ज्यादा सिर आ रहे हैं, मस्तिष्क नहीं। जाति, धर्म, स्वार्थ और वर्ग के मुछोटे ज्यादा हैं, मनुष्यता के चेहरे कम। तभी राजनीति अवसरवादिता का अखाड़ा बनती जा रही है।

●●●●●

मारुति डिजायर और टाटा टिगोर को चुनौती देने होण्डा ला सकती है एमेज का नया वर्जन

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय बाजार में Compact Sedan के तौर पर Honda की ओर से Amaze को ऑफर किया जाता है। मारुति डिजायर टाटा टिगोर और हुंडई ऑरा को चुनौती देने के लिए कंपनी की ओर से जल्द ही इस गाड़ी का नया वर्जन लाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा कब तक इसे ला सकती है और इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में जहां एक ओर एसयूवी सेगमेंट के साथ ही हैचबैक कारों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। वहीं कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में भी मारुति डिजायर, टाटा टिगोर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Honda Amaze का नया वर्जन लाने की तैयारी की जा रही है। हम इस

खबर में आपको बता रहे हैं कि कंपनी की ओर से कब तक अमेज का नया वर्जन किन बदलावों के साथ लाया जा सकता है।

Honda Amaze का आएगा नया वर्जन होडा की ओर से भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट सेडान के तौर पर अमेज को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस कार के नए वर्जन को लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी कंपनी की ओर से इसके बारे में किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल में फेस्टिव सीजन के शुरू होने से पहले इसे पेश किया जा सकता है।

क्या होंगे बदलाव
रिपोर्ट्स के मुताबिक नई अमेज में कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे। जिसमें गाड़ी को फ्रंट और रियर से बदला जा सकता है। इसके साथ ही इसमें कई नए फीचर्स को भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके इंजन में कोई खास बदलाव होने की संभावना कम है। नई अमेज को होडा सिटी की पांचवी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जा सकता है। इसके साथ ही इसे ग्लोबल स्तर पर ऑफर की जाने वाली सेडान कार Civic और Accord की तरह डिजाइन किया जा सकता है।



इलेक्ट्रिक दोपहिया का निर्यात हब बन सकता है भारत, दुनिया में मांग बढ़ने की उम्मीद

इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में चीन की कंपनियों की रुचि घरेलू कार बाजार पर ज्यादा है। जापान की कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन उनके पास विस्तार करने की योजना अभी तक नहीं है। ऐसे में भारतीय दोपहिया कंपनियों के पास अवसर है कि वह इस स्थिति का फायदा उठाकर वैश्विक दोपहिया ईवी की प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकती हैं।

दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसमें भारत की दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Two Wheeler) बनाने वाली कंपनियों के लिए जबरदस्त संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दक्षिण अमेरिकी देशों से लेकर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग बढ़ रही है, लेकिन इनकी आपूर्ति करने वाली कंपनियों की कमी है।

निर्यात हब बन सकता है भारत
इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में चीन की कंपनियों की रुचि घरेलू कार बाजार पर ज्यादा है। जापान की कंपनियों के पास प्रौद्योगिकी है लेकिन उनके पास विस्तार करने की योजना अभी तक नहीं है। ऐसे में भारतीय दोपहिया कंपनियों के पास अवसर है कि वह इस स्थिति का फायदा उठाकर वैश्विक दोपहिया ईवी की प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकती हैं। भारतीय कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष कुछ सौ दोपहिया वाहनों का ही निर्यात किया है, लेकिन अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत से 10 लाख से ज्यादा दोपहिया वाहनों का निर्यात हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय ईवी कंपनियों को सब्सिडी देने के साथ ही विदेशी बाजारों में पैर पसारने के लिए भी हरसंभव मदद दी जा रही है।

मांग बढ़ने की उम्मीद

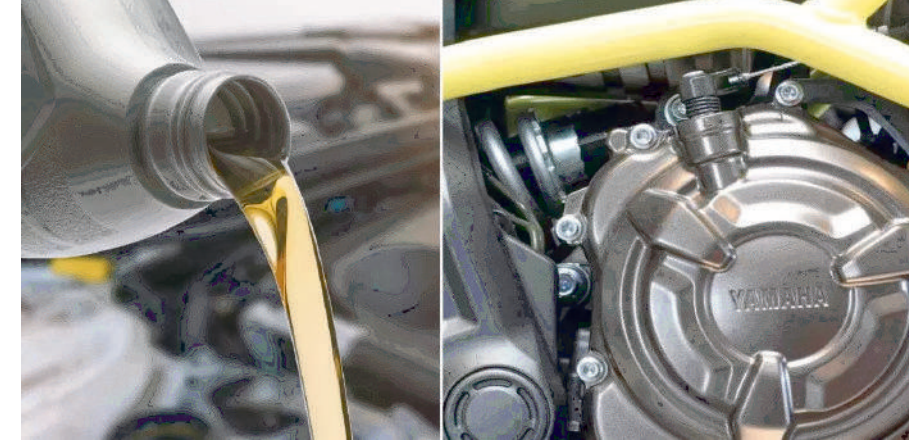


पिछले दिनों नीति आयोग और भारी उद्योग व लोक उपक्रम मंत्रालय की अगुआई में ईवी क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति में संभावनाओं पर एक बैठक हुई। बैठक में शामिल उद्योग जगत के कुछ लोगों ने दैनिक जागरण को बताया कि अगर कार बनाने वाली कुछ दिग्गज वैश्विक कंपनियां भारतीय बाजार में उतरने की तैयारी में हैं तो दोपहिया बाजार में भारतीय कंपनियों की भी बहुत जबरदस्त मांग बढ़ने की सूरत बन रही है। सरकार इस बारे में व्यापक अध्ययन करने में कंपनियों को मदद करेगी। अभी तक जो सूचना सामने आई है उसके मुताबिक, पिछले छह महीनों में चीन की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने दोपहिया वाहनों के निर्यात पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। वजह यह है कि उनके घरेलू बाजार में

इलेक्ट्रिक कारों की मांग उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। उसके लिए कल-पुर्जे आपूर्ति करने में इन कंपनियों को ज्यादा फायदा दिख रहा है। भारत के लिए एक शुभ संकेत यह है कि दक्षिण अमेरिकी व अफ्रीका के जिन बाजारों में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग निकल रही है वहां भारत की पेट्रोल चालित वाहनों की पहले से ही काफी अच्छी साख है। बजाज आटो, टीवीएस व हीरो के स्कूटर व मोटरसाइकिल इन बाजारों में चीन की दोपहिया कंपनियों को पहले ही बाहर कर चुकी हैं। ये कंपनियां आसानी से अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को इन बाजारों में बेच सकती हैं। नीति आयोग ने कहा, मौजूदा निर्माण क्षमता का करना होगा विस्तार कुछ महीने पहले भारत की एक प्रमुख दोपहिया वाहन कंपनी एथर

एनर्जी ने नेपाल के बाजार में प्रवेश किया है। नीति आयोग ने भारतीय कंपनियों को कहा है कि विदेशी बाजार में उपलब्ध संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए उन्हें अपनी मौजूदा निर्माण क्षमता का विस्तार करना होगा। अभी भारतीय बाजार में ही काफी ज्यादा मांग होने की संभावना है। वर्ष 2019-20 में भारत में सिर्फ 28 हजार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व्हीकल की बिक्री हुई थी, जो वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 7.28 लाख हो गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान बिक्री में तीन गुणा वृद्धि की संभावना जताई गई है। ऐसे में भारतीय कंपनियों जैसे एथर, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो इलेक्ट्रिक, ओकीनावा आटोटेक, बजाज आटो आदि को अपनी क्षमता में भारी विस्तार करना होगा। लेकिन इसके साथ ही इन्हें विदेशी बाजार को लेकर भी नीति सामने लानी होगी।

बाइक का इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए, किन बातों से लगाएं पता, जानें डिटेल



किसी भी बाइक के लिए इंजन का सही तरह से काम करना काफी जरूरी होता है। अगर इंजन में किसी भी तरह की खराबी आ जाती है तो फिर उसे ठीक करवाने में समय और पैसे दोनों लगते हैं। Bike के इंजन को सही रखने के लिए Engine Oil का सही समय पर बदलना भी जरूरी होता है। इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। किसी भी Bike के लिए इंजन काफी जरूरी पार्ट होता है। इंजन को सही रखने और लंबे समय तक बिना परेशानी चलाने के लिए समय पर Engine Oil का बदलना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। किन संकेतों के जरिए इस बात की जानकारी मिलती है कि बाइक के इंजन

ऑयल को बदला जा सकता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

इंजन से आवाज
अगर आपकी बाइक को चलाते हुए इंजन से सामान्य से ज्यादा आवाज आने लगती है, तो ऐसी स्थिति में इंजन ऑयल को बदलना काफी जरूरी हो जाता है। जब भी बाइक में नया इंजन ऑयल डाला जाता है तो इंजन की आवाज काफी कम हो जाती है, लेकिन जब भी ऑयल खराब हो जाता है तो इंजन से आने वाली आवाज बढ़ने लगती है।

ओवरहीट होने पर भी चेक करें

अगर आपकी बाइक चलते हुए काफी तेजी से ओवरहीट होने लगती है, तो भी इस बात की संभावना होती है कि इंजन ऑयल खराब हो गया हो। इसके साथ ही यह भी खतरा

होता है कि इंजन में ऑयल का स्तर काफी कम हो गया हो। ऐसा होने पर इंजन को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे संकेत मिलने पर इंजन ऑयल को चेक कर उसे बदल देना चाहिए।

पढ़ें मैनुअल बुक
हर बाइक के साथ कंपनी की ओर से मैनुअल बुक या ई-मैनुअल को दिया जाता है। जिसमें इस बात की जानकारी होती है कि बाइक में किस तरह के इंजन ऑयल का उपयोग करना चाहिए और इसे कब बदलना चाहिए। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाकर भी अपनी बाइक के इंजन ऑयल को बदलने की जानकारी को लिया जा सकता है। कई बाइक्स में कंपनियों की ओर से हर तीन हजार किलोमीटर पर इंजन ऑयल बदलने की सलाह दी जाती है।

मार्च महीने में देश में सबसे ज्यादा हुई इन कारों की बिक्री, जानें टॉप-5 में कौन सी कारें हुई शामिल

भारतीय बाजार में हर महीने लाखों की संख्या में वाहनों की बिक्री होती है। जिनमें यात्री वाहन सेगमेंट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। March 2024 के दौरान देशभर में ग्राहकों ने Cars and SUVs को सबसे ज्यादा पसंद किया। बिक्री के मामले में Top 5 लिस्ट में कौन कौन सी कारों और एसयूवी ने अपनी जगह बनाई है। आइए जानते हैं।



नई दिल्ली। March 2024 के दौरान देशभर में बड़ी संख्या में कारों और एसयूवी सेगमेंट में बिक्री हुई। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि बिक्री के मामले में बीते महीने में किन पांच (Top 5 Cars) कारों को सबसे ज्यादा पसंद किया गया।

Tata Punch बनी पहली पसंद

मार्च 2024 के दौरान कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा की पंच एसयूवी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। कंपनी की इस एसयूवी की बीते महीने में कुल 17547 यूनिट्स की बिक्री देशभर में हुई है। टाटा की ओर से सबसे सस्ती एसयूवी के तौर पर पेश की जाने वाली पंच की शुरूआती एक्स शोरूम कीमत 6.13 लाख रुपये है।

Hyundai Creta की भी रही मांग

हुंडई की ओर से क्रेटा को एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। बीते महीने इस एसयूवी को भी 16458 ग्राहकों ने खरीदा। जबकि पिछले साल इसी अवधि में इस एसयूवी की कुल 14026 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। भारत में इस एसयूवी की एक्स शोरूम कीमत की शुरूआत 10.99 रुपये से हो जाती है।

Maruti Wagon R की तीसरे नंबर पर
देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता

मारुति की ओर से हैचबैक कार के तौर पर वैगन आर को ऑफर किया जाता है। लंबे समय से भारतीयों की पसंदीदा कार के तौर पर वैगन आर रही है। बीते महीने इस कार की कुल 16368 यूनिट्स की बिक्री हुई है। बाजार में इस कार की एक्स शोरूम कीमत की शुरूआत 5.54 रुपये से हो जाती है।

Maruti Dzire
मारुति की ओर से कॉम्पैक्ट सेडान के तौर पर डिजायर को ऑफर किया जाता है। कंपनी की यह सेडान कार अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। बीते महीने में इस कार की 15894 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि इसके पहले मार्च 2023 में इसकी 13394 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। इस कार की शुरूआती एक्स शोरूम कीमत 6.56 लाख रुपये से शुरू होती है।

पांचवें नंबर पर रही Maruti Swift
मारुति की ओर से हैचबैक के तौर पर स्विफ्ट को भी ऑफर किया जाता है। यह कार युवाओं को काफी ज्यादा पसंद आती है। बीते महीने में इस कार की कुल 15728 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि इसके पहले इस कार की 17559 लोगों ने खरीदा था। इसकी कीमत की शुरूआत 5.99 लाख रुपये से हो जाती है।

विकसित भारत की दरकार है खुशहाली



डा . जयंती लाल भंडारी

यद्यपि जून 2024

में गठित होने

वाली नई सरकार

के मूर्तरूप लेने में

दो माह बाकी हैं,

लेकिन 2047 में

विकसित भारत

के लक्ष्य के तहत

आम आदमी की

खुशहाली बढ़ाने

की जरूरत के

मद्देनजर अभी से

प्रशासनिक स्तर

पर रणनीति

बनाई जाना शुरू

हो गई है।

हैं यह ध्यान रखना होगा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित देश बनाने के लिए सरकार के द्वारा आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय और खुशहाली बढ़ाने के लिए जो व्यय किए जाते हैं, वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जिस तरह सरकार के द्वारा बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश लाभप्रद होता है। उम्मीद है सरकार रणनीतिक रूप से कारगर प्रयासों की राह पर आगे बढ़ेगी।

यद्यपि जून 2024 में गठित होने वाली नई सरकार के मूर्तरूप लेने में दो माह बाकी हैं, लेकिन 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य के तहत आम आदमी की खुशहाली बढ़ाने की जरूरत के मद्देनजर अभी से प्रशासनिक स्तर पर रणनीति बनाई जाना शुरू हो गई है। देश के आम आदमी के जीवन स्तर में वृद्धि, गरीबी में कमी, रोजगार के मौके बढ़ाने जैसे विभिन्न मुद्दों पर अधिक प्रयासों से ही देश खुशहाली के उस स्तर पर पहुंच सकता है, जोकि विकसित भारत की महत्वपूर्ण दरकार है। इस परिप्रेक्ष्य में हाल ही में 21 मार्च को प्रकाशित विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है, जिसमें 143 देशों में भारत को 126वां स्थान दिया गया है। गौरतलब है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के तहत सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण जैसे कारकों के आधार पर विश्व भर के देशों का आकलन कर रैंकिंग तैयार की गई है। पिछले वर्ष भी इस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर था। इस रैंकिंग में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है।

नॉर्डिक देश खुशहाली सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। इनमें डेनमार्क और आइसलैंड ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। स्वीडन चौथे नंबर पर है। यद्यपि इस वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद दुनिया के कोने-कोने से लोग इसे आतंकिंक और अविश्वसीय बनाते हुए टिप्पणीयां कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूरोपीय विद्वानों के द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदण्डों पर आधारित खुशहाली की रैंकिंग देने वाली यह सूची भ्रमित करने वाली है। इस रैंकिंग पर भरोसा नहीं होता है। इस खुशहाली की रैंकिंग में भारत से चार पायदान ऊपर 122वें पर स्थित पाकिस्तान दुनियाभर में तहगाई, ऋणग्रस्तता, धार्मिक आजादी व लोकतांत्रिक चुनौती से ग्रस्त ऐसे देश के रूप में वर्णित है जिस देश की सत्ता में सांप्रदायिक कट्टरपंथी जमात अग्रिम पंक्ति में है। कदम-कदम पर



धार्मिक पाबंदियों वाला कुवैत दुनिया का 13वां सबसे खुशहाल देश है। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के साथ निर्मित युद्ध से जिस देश के हजारों लोगों के चेहरों पर निराशाएं दी हैं, उस इजराइल को दुनिया का पांचवां सबसे खुशहाल देश बताया गया है। इतना ही नहीं, युद्ध से पीड़ित क्षतिग्रस्त, हजारों मौतों का सामना कर रहा रूस 72वें, फिलस्तीन 103वें तथा यूक्रेन 105वें क्रम पर है। ये देश पीड़ाओं, निराशाओं व युद्ध के बावजूद भारत से अधिक खुशहाली की रैंकिंग दर्शा रहे हैं। इस विश्व खुशहाली रिपोर्ट में बेमेल गणनाएं की गई हैं। इस सूची के तहत दुनिया की सबसे अधिक आबादी रखने वाले भारत और भारत की आबादी से एक फीसदी से भी बहुत कम आबादी रखने वाले देशों की जनसंख्या चुनौतियों व समस्याओं के मद्देनजर तुलनाएं करते हुए भी खुशहाली की गणना की गई है। प्रश्न यह है कि भारत जैसे दुनिया की बड़ी आबादी के साथ दुनिया के सातवें सबसे बड़े भूभाग रखने वाले भारत की तुलना दुनिया के छोटे-छोटे कम आबादी व कम चुनौतियां रखने वाले देशों से कैसे की जा सकती है? खुशहाली को महज आर्थिक प्रगति और संसाधनों की अधिकता के मद्देनजर देखा जाना उपयुक्त नहीं है।

जिन कई देशों को दुनिया के अधिक खुशहाल देश बताया गया है, वहां आबादी बहुत कम है, चुनौतियां भी बहुत कम हैं तथा धार्मिक विद्वेष भी नहीं है। ऐसे कई छोटे देशों की सरकारों को किसी समस्या को सुलझाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे देशों की तुलना बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे विशाल देशों से कैसे की जा सकती है? इस

वैश्विक खुशहाली सूची में भारत के संबंध में कुछ ऐसे विश्व स्तर पर चमकीले परिदृश्य को ध्यान में नहीं रखा गया है जिनके लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक सहित दुनिया के कई आर्थिक-सामाजिक संगठन अपने शोध पत्रों के आधार पर भारत में नए प्रयासों की सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में मानव विकास के तहत गरीबी में कमी लाने के प्रयास को भारी सफलता मिली है। पिछले एक दशक में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पूरी दुनिया में रेखांकित हो रहा है कि भारत आम आदमी को डिजिटल दुनिया से जोड़ने वाला दुनिया का प्रमुखतम देश है। भारत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। भारत में सरकार के द्वारा गरीबों व किसानों के बैंक खातों में सीधे 32 लाख करोड़ से अधिक धनराशि भेजकर उनका सकलितकरण किया गया है। चाहे खुशहाली के सूची में विभिन्न देशों की रैंकिंग अनुचित और अन्यायपूर्ण ढंग से की गई है, लेकिन हमें भारत में आम आदमी के आर्थिक कल्याण, आम आदमी की आमदनी बढ़ाने तथा खुशहाली के विभिन्न पैमानों पर बहुत आगे बढ़ने के लिए अभी मीलों चलना है। हमें भारत में खुशहाली बढ़ाने व आय असमानता के बड़े अंतर को कम करने के लिए बड़े प्रयास करने हैं। 121 मार्च को प्रकाशित न्यूयांक यूनिवर्सिटी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022-23 में भारत की कुल आय का 22.6 फीसदी हिस्सा सबसे अमीर एक फीसदी लोगों के पास गया। वर्ष 2022-23 में देश की सबसे अमीर एक फीसदी आबादी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 39.5 फीसदी हिस्सा था, जबकि सबसे गरीब

जारी मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) रिपोर्ट 2022 में भारत 193 में से 134वें स्थान पर है। यद्यपि भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की एचडीआई-2021 रिपोर्ट के मुकाबले एक

पायदान का सुधार हुआ है। भारत पिछले 34 वर्षों से 131 से 135वें स्थान पर झूल रहा है। एचडीआई का तात्पर्य मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों- लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और सभ्य जीवन स्तर में औसत उपलब्धियों के आकलन से है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र ने नए मानव विकास सूचकांक में भारत की औसत बढ़त को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा है। पिछले एक वर्ष में भारतीयों की औसत आमदनी में 6.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। भारत में जीवन प्रत्याशा में शानदार वृद्धि हुई है। एक वर्ष पहले भारत में जीवन प्रत्याशा का औसत 62.2 था जो अब बढ़कर 67.7 हो गया है। भारत ने लैंगिक असमानता को कम करने में भी प्रगति प्रदर्शित की है। भारत में लिंग असमानता सूचकांक वैश्विक औसत से बेहतर है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित देश बनाने के लिए सरकार के द्वारा आम आदमी की प्रतिव्यक्ति आय और खुशहाली बढ़ाने के लिए जो व्यय किए जाते हैं, वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जिस तरह सरकार के द्वारा बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश लाभप्रद होता है। हम उम्मीद करें कि देश में करोड़ों लोगों की गरीबी, भूख, कुपोषण, डिजिटल शिक्षा, रोजगार, उर्ध्वमान, ग्रामीण युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण और स्वास्थ्य की चुनौतियों को कम करने के लिए सरकार की रणनीतिक रूप से, हरसंभव तरीके से कारगर प्रयासों की डार पर तेजी से आगे बढ़ेगी।

मोदी की गारंटी बनाम कांग्रेस का न्याय

सुरेश हिंदुस्तानी

अब जब लोकसभा चुनाव के मैदान सज गया है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने बयानों में पैनापन लाने की क़वायद कर रहे हैं, तब यह तो कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव कई दलों के लिए आरपाार की लड़ाई हो गई है।

लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच सभी राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को प्रभावी बनाने के उद्देश्य को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं विपक्षी राजनीतिक दल केवल वर्तमान सत्ताधारी दल के विरोध पर ही अपना पूरा फोकस करते हुए चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि भाजपा ने जहां मोदी की गारंटी को प्रमुख हथियार बनाकर अपने मन में विश्वास बनाया है, वहीं अब कांग्रेस भी इसका अनुसरण करने की नीति अपना रही है। भाजपा की ओर से मोदी की गारंटी के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी पार्टी की 25 गारंटी जनता के सामने लाए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम देकर एक नई राह बनाने का काम किया है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस ने न्याय देने के वादे पर ही लड़ा था, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। हम जानते हैं कि भाजपा ने 2014 के चुनाव में भारत के चाय वालों के साथ गहरा संबंध स्थापित किया था, इसी प्रकार 2019 के चुनाव में कांग्रेस के चौकीदार चोर हैं के जवाब में "मैं भी चौकीदार" का नारा देकर गरीब तबके को अपने साथ जोड़ा था। इस चुनाव में मोदी की गारंटी भाजपा का नारा है। कांग्रेस ने भी गारंटी देने का वादा किया है, लेकिन जनता किसकी गारंटी

को स्वीकार करती है, यह समय बताएगा।

मैं इस लेख को किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जो सच है उसको लिखने से कोई आशय निकलता है तो भले ही निकले, लेकिन उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कांग्रेस की योजनाओं की नाकामी को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था कि सरकार गरीब जनता तक जो लाभ पहुंचाती है, उसका मात्र 15 प्रतिशत ही पहुँच पाता था। इसका आशय यह भी है कि 85 प्रतिशत राशि या तो कमीशान खोरी में जाता था या प्रशासनिक अयव्यवस्था की भेंट चढ़ जाता था। इसका एक अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि कांग्रेस के शासन काल में हर शासकीय योजना भ्रष्टाचार का शिकार हुई। इसके विपरीत वर्तमान केंद्र सरकार में कम से कम इतना तो हुआ ही है कि गरीब तक पहुँचने वाला लाभ बिना किसी बिचौलिए के पात्र व्यक्ति को ही शत प्रतिशत मिल रहा है। यानी अब योजनाएं बिना किसी भ्रष्टाचार के पूरी हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से दी जाने वाली गारंटी निश्चित ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल में बढ़ोत्तरी करेगी। क्योंकि अब उनके पास भी जनता के बीच अपनी योजनाएं रखने के लिए मौका है। कांग्रेस के यह बात भी एक संजीवनी का कार्य कर रही है कि उसके नेता राहुल गांधी जनता के बीच जाने के लिए बहुत तेजी से सक्रिय होते जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कांग्रेस को केवल मोदी विरोध की राजनीति से तौबा करना चाहिए, उसे केवल जनता के बीच जाकर अपने वादे बताकर जनता से संबंध बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी शैली होती है। मोदी की शैली यही है कि



वह जनता की भावना के अनुसार ही अपना भाषण देते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी कभी कभी पटरी से उतरते दिखाई देते हैं। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में न्याय देने की बात कही गई है। साथ ही जातिगत जनगणना करने का भी वादा किया गया है। हो सकता है जातिगत जनगणना का वादा कांग्रेस के लिए लाभकारी साबित हो, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि इस मुद्दे पर भारत की पूरी जनता आँख बंद करके समर्थन करने के लिए आगे आ जाए। क्योंकि जो संस्थान या व्यक्ति समाज को एक करके के लिए प्रयास करेगा ही नहीं, उनको कांग्रेस का यह वादा न्यायसंगत नहीं लग रहा होगा। यह बात सही है कि आज समाज बदल रहा है। वह जातिगत समाज के बाहर आकर भारतीय समाज यानी एकत्रित समाज होने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस का यह कदम समाज में विभाजन की लकीर खींचने का काम कर सकता है।

इस देश के अनेक चुनावों में यह देखने को



मिला है कि विपक्षी दल महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने का अभियान स चलाते थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में मेहंगाई थी, इसी प्रकार बोफोर्स मामले को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने चुनाव लड़ा, जिसमें राजीव गांधी की सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। आज विपक्ष के पास सरकार के विरोध में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, जिस पर सरकार को घेरा जा सके। इसके विपरीत सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह राजनीति की दशा और दिशा को बदलने वाला दृश्य कहा जा सकता है। यह पहला चुनाव कहा जा सकता है, जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घर रहा है। विपक्ष के कुछ दल इस मामले में मौन साधे हुए हैं, क्योंकि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वे या उनके साथी उनके साथ हैं। इससे यह भी साफ संकेत जाता है कि भ्रष्टाचार के विरोध में विपक्ष की कोई योजना नहीं है। मोदी सरकार के दस साल के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जबकि विपक्ष

आज भी आरोप लग रहे हैं। कई तो जमानत पर बाहर हैं।

अब जब लोकसभा चुनाव के मैदान सज गया है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने बयानों में पैनापन लाने की क़वायद कर रहे हैं, तब यह तो कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव कई दलों के लिए आरपाार की लड़ाई हो गई है। जो राजनीतिक दल सत्ता सुख से लम्बे समय से दूर हैं, वह बेचैन से हो रहे हैं। हालांकि यह भी एक बड़ा सच है कि सत्ता पक्ष को निरंकुश होने से बचाने के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन यह भी सत्य है कि विपक्ष को मजबूत करने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से प्रयास नहीं किए जाते। इसके लिए स्वयं विपक्ष को ही प्रयास करना होगा। विपक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार विपक्ष को कमजोर कर रही है, ऐसा आरोप लगाना विपक्ष की कमजोरी को ही दर्शाता है। इसलिए विपक्ष को अब एक ताकत के रूप में अपने आपको प्रस्तुत करना होगा।

- सुरेश हिंदुस्तानी,

ज्ञान शव संवाद-38

पहली बार बुद्धिजीवी ने एक ऐसा परिंदो देखा जो वाकई पर नहीं मार रहा था। बुद्धिजीवी यह देख सोच में पड़ गया कि यह अपने पंख होते हुए भी आखिर उड़ क्यों नहीं पा रहा है, 'यह जरूर किसी से टकराया होगा। कहां टकराया होगा। अदालत के दरवाजे या संसद के गुंबद से।' देखने में परिंदो तंदरुस्त था। तरह-तरह की बोली बोल रहा था। हरकते कर रहा था, लेकिन अपने पर नहीं खोल पा रहा था। पहली बार बुद्धिजीवी ने इनसान जैसी असमंजस किसी पक्षी में देखी। देश की असमंजस पक्षी पर नहीं बरसती थी कि वह न कराह सकता था और न ही शिकायत कर सकता था। शिकायत करे भी तो किसकी और करे भी तो कहां। जहां इनसानों की शिकायतें मुर्दा हो रहीं, वहां पंछी की कौन सुनाने। बुद्धिजीवी ने सहजता से उसके पर हिलाला। इस कार्य में वह सिद्धहस्त है। बचपन से दूसरों के पर हिलाते-हिलाते ही तो वह बुद्धिजीवी बना, वरना कभी अपने भी टटोल लेता। उस याद है कि शिक्षा को सरकारों ने हर बार नए-नए पर लगाए, लेकिन आज तक यह पर नहीं मार सकी। बिना परों के उसने देश को उड़ते देखा। कितनी बार देखा कि नेताओं ने आसमान सिर पर उठाया है। उनके वजूद को जिंदा रखने के लिए पर दौड़ते रहे हैं और आज भी आसमान में पर ही पर हैं। वह एक पर पंछी को देखाता, दूसरें परल आसमान में उड़ते पर देखता। यह परों का विश्वासघात था जो पंछी को उड़ने से र्वंचित करके, खुद आसमान पर थे। परों के ऊपर कितने ही नारे थे। दौड़ते पर बता रहे थे कि देश भी अब व्यक्ति है, नेता है, अभिनेता है, सपना है, इश्वर है, जाति है, वर्ग है, धर्म है और जरूरत पड़ने पर सिर्फ अतीत में खड़ा रह सकता है। पर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन देश की खातिर मर रहे थे। बुद्धिजीवी आश्चर्यचकित था कि जिस देश की सत्ता इतनी बलुंद है कि पंछी पर नहीं मार सकता, वहां पर बता रहे हैं उन्होंने इसे कैसे बुलंद किया। खैर बुद्धिजीवी प्रयास करके परों के झुंड से कुछ पंख छीनकर पंछी को पहनाने की कोशिश करने लगा, ताकि देश को उड़ाने वाले, उसे भी उड़ा दे, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। जो पर किसी पंछी को नहीं उड़ा पा रहे थे, वे देश को सातवें आसमान पर पहुंचा रहे थे। यह देश वाकई कितना महान है, यह पंछी की हालत देखकर पता चल रहा था। देश में इतनी ताकत है कि पंछी को जमीन पर बैठा दे और किसी को भी आसमान पर उड़ा दे। बुद्धिजीवी ने तय कर लिया कि फिर से वह पंछी को आसमान पर और कटे परों को धरती पर लाएगा। वह संसद के समक्ष पंछी को पंखों पर उड़ाने की तरकीब पूछता है, तो भीतर से गृह मंत्री की आवाज आती है, 'देश चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है, लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था के आगे कोई भी पंछी पर नहीं मार सकता। हमने समस्त सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है और अगर किसी को शक है तो पंछियों का मुआयना करके देखें कि भारत में किस कदर वे पंख नहीं मार सकते हैं।' तभी बुद्धिजीवी के हाथ में आया पंछी चीख उठा, 'मुझे यहाँ से दूर ले चलो। यहाँ सरकार की लाल आँख मुझे उड़ने नहीं देगी। जब से सरकार विदेशी ताकतों को लाल आँख दिखा रही है, पंछी पर मारना शुरू रहा है। हमारी असमर्थता की वजह लाल आँख है।' बुद्धिजीवी ने तभी देखा कि 'लाल आँख' उसके पीछे आ रही है। पंछी सहित वह भी भागने लगा। उसके साथ हजारों कटे पर भी जान बचाकर भागने लगे। लाल आँख उन्हें वहीं छोड़ आई, जहाँ से वे चले थे। बुद्धिजीवी ने एक जिंदा पंछी के मरे हुए पर को उठाया और सोचा कि इसके शव का दहन कर मोक्ष प्राप्त करवाऊँ। रास्ते में मरे हुए पर का शव बोला, 'जानते हो मैंने देश के लिए बलिदान दिया है।

अनन्या मिश्रा

प्रभु राम की नगरी अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की प्राण-प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बेहद धूमधाम से मनाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामलला को जो आभूषण पहनाए गए हैं, उनका रत्नों का ज्योतिष से कनेक्शन है।

प्रभु राम की नगरी अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की प्राण-प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बेहद धूमधाम से मनाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामलला को जो आभूषण पहनाए गए हैं, उनका रत्नों का ज्योतिष से कनेक्शन है। आपको बता दें कि ज्योतिषाचार्यों ने रामलला के गहनों को अंक ज्योतिष से जोड़कर उनकी गणना प्रस्तुत की है। जिसमें रामलाल द्वारा पहने गए रत्नों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऐसे में अगर आप भी इन रत्नों के ज्योतिष कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल

आपके लिए है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामलला के आभूषणों में 3,6,9, 12 जैसे विभिन्न शुभ अंक शामिल हैं। यह सभी हर अलग-अलग पहलु को दर्शाने का काम करते हैं। इन गहनों के जटिल विवरण पर भी प्रकाश डाला गया है। इनमें इस्तेमाल किए गए सोने, पन्ने और हीरे आदि का वजन शामिल है। वहीं रामलला के दिव्य मुकुट के बारे में भी अंक ज्योतिष में विस्तार से वर्णन किया गया है और इसमें प्रतीकवाद पर भी जोर दिया गया है।

रामलला की मूर्ति और आभूषण
रामलला की मूर्ति 51 इंच की है। यदि आप 5+1 करते हैं तो यह 6 होता है। इसके अलावा रामलला के आभूषण बनाने में 51 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है। 15+1=6
रामलाल के पूरे आभूषणों में 18,000

कैरेट के पन्ने और हीरे का मिश्रण है।

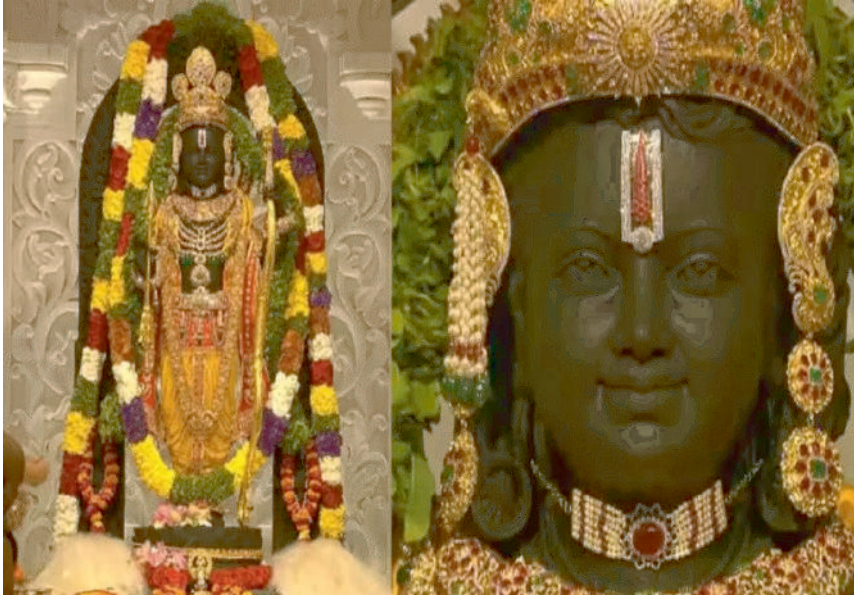
1+8=9

वहीं रामलला ने जो दिव्य मुकुट धारण किया है, यह 1.71 किलोग्राम और 22 कैरेट सोने का है। 1+7+1=9

पारखी और बारीक नजर से चुने गए रामलला के ताज में 261 कैरेट माणिक्य लगे हैं, जिससे ताज को एक अद्वितीय चमक मिलती है। 12+6+1=9

रामलला का मुकुट सूर्यदेव की छवि से सुशोभित है। साथ ही यह सूर्यवंशियों के शाही वंश को भी दर्शाने का काम करता है। तो यदि आप ध्यान दें तो एक साल में सूर्य के 12 दिव्य रूप होते हैं।
उन्के मुकुट में 75 कैरेट के बारीक हीरे जड़े हैं। 17+5=12

इसके साथ रामलला के क्राउन में एक विशेष खदान के 174 बढिया पानी के विशोषन पन्ने हैं। 1+7+4=12



भारतीय सीईओ के औसत वेतन में भारी बढ़ोतरी, कोविड-19 महामारी के बाद 40 फीसदी तक बढ़ी सैलरी

परिवहन विशेष न्यूज

किसी भी कंपनी में सीईओ का पद बहुत जरूरी होता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सीईओ की सैलरी को लेकर सवाल होते हैं। भारतीय सीईओ की सैलरी को लेकर डेलॉइट (Deloitte) ने एक रिपोर्ट पेश किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सीईओ का औसत वेतन 13.8 करोड़ रुपये है। यह कोविड-19 से पहले के तुलना में 40 फीसदी अधिक है।

नई दिल्ली। किसी भी कंपनी के सीईओ के पास कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कई लोग यह भी जानने में इच्छुक रहते हैं कि आखिर सीईओ की सैलरी कितनी होती है।

भारतीय सीईओ यानी चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर की सैलरी को लेकर डेलॉइट ने एक रिपोर्ट पेश किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सीईओ का औसत वेतन 13.8 करोड़ रुपये है। यह कोविड-19 से पहले की तुलना में 40 फीसदी अधिक है। इसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इंस्टेंव है।

डेलॉइट इंडिया एक्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस एंड रिवाइर्स सर्वे 2024 (Deloitte India Executive Performance and Rewards Survey 2024) के अनुसार, सीईओ का औसत कंपनसेशन

13.8 करोड़ रुपये है। इसमें सीईओ प्रमोटर या प्रमोटर परिवार के सदस्य भी थे। इन्हें औसतन 16.7 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है।

प्रमोटर सीईओ का कंपनसेशन पेशेवर सीईओ के कंपनसेशन से ज्यादा है। कुल मिलाकर प्रमोटर सीईओ के लंबे कार्यकाल के कारण प्रमोटर सीईओ की तुलना में पेशेवर सीईओ अधिक बार बदलते हैं।

डेलॉइट इंडिया के पार्टनर, सीएचआरओ प्रोग्राम लीडर, आनंदोरूप घोष ने कहा

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रमोटर सीईओ कंपनसेशन की सीमा बहुत व्यापक है। कई बड़ी भारतीय कंपनियां प्रदर्शन शेरों की ओर ध्यान दे रही हैं और विभिन्न कर्मचारी समूहों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाओं का उपयोग कर रही हैं।

डेलॉइट के रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ कंपनसेशन में वृद्धि हुई है। यह लक्ष्य कंपनसेशन का 50 प्रतिशत से अधिक 'Pay At Risk' है। पेशेवर सीईओ के लिए 57 प्रतिशत पर जोखिम भुगतान, प्रमोटर सीईओ के लिए 47 प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक है।

पेशेवर सीईओ को उनके लक्ष्य कंपनसेशन का 25 प्रतिशत दीर्घकालिक प्रोत्साहन के माध्यम से दिया जाता है। कई कंपनियों के लिए शेयर-लिंकड प्रोत्साहन के



माध्यम से भुगतान किया जाता है।

डेलॉइट के अनुसार भारत में सीईओ कंपनसेशन में उच्च-एकल-अंकीय वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यम और औसत सीईओ कंपनसेशन के बीच व्यापक अंतर (9.3 करोड़ रुपये बनाम 13.8 करोड़ रुपये) कंपनसेशन की संख्या की विस्तृत श्रृंखला और उच्च स्तर पर कुछ आउटलेसों को इंगित करता है।

सीईओ और सीएक्सओ के प्रदर्शन का आकलन करते समय अधिकांश कंपनियां एक समग्र स्कोरकार्ड का उपयोग करती हैं जिसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय मैट्रिक्स और लक्ष्यों का मिश्रण शामिल होता है। हालाँकि, सीईओ और सीएक्सओ के लिए प्रोत्साहन अभी भी उन स्कोरकार्ड के भीतर वित्तीय कंपनी-स्तरीय लक्ष्यों की ओर झुका हुआ है। डेलॉइट ने कहा कि शेयर-आधारित

प्रोत्साहनों का उपयोग करने वाली कंपनियों का प्रतिशत बढ़ रहा है।

डेलॉइट इंडिया एक्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस एंड रिवाइर्स सर्वे का पांचवां संस्करण सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। इस बी2बी भारत-विशिष्ट सर्वेक्षण में 400 से अधिक संगठनों ने भाग लिया, जिसमें कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी शामिल नहीं थी।

यूट्यूबर पर चला सेबी का चाबुक; 12 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश, मार्केट से भी किया बैन

परिवहन विशेष न्यूज

यूट्यूबर रवींद्र भारती और उनकी पत्नी शुभांगी ने 2016 में रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड (RBEIPL) की नींव रखी थी। रवींद्र के दावे के मुताबिक- उनकी कंपनी लोगों को शेयर बाजार में निवेश का तरीका सिखाती थी। लेकिन सेबी ने अपनी जांच में पाया कि रवींद्र की कंपनी अपनी सलाह से निवेशकों को गुमराह करती थी। यह निवेशकों को 1000 प्रतिशत तक के रिटर्न का लालच दे रही थी।

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर अक्सर लोगों को तगड़े मुनाफे का लालच देकर शेयर मार्केट में निवेश करने की सलाह देते हैं। बहुत से लोग उनकी बातों में आकर निवेश कर देते हैं और बाद में उन्हें भारी नुकसान होता है। इस तरह के मामलों को लेकर मार्केट रगुलेटर सेबी (SEBI) काफी सख्त रहता है। उसने ऐसे ही एक मामले में यूट्यूब 'इंफ्लुएंसर' रवींद्र बालू भारती की अगुवाई वाले रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है।

मार्केट सेबैन, 12 करोड़ का जुर्माना

सेबी ने रवींद्र बालू और उनके इंस्टीट्यूट को कैपिटल मार्केट में निवेश करने से बैन कर दिया है। साथ ही, उन्हें 12 करोड़ रुपये लौटाने का भी आदेश दिया है, जो उन्होंने गैरकानूनी तरीके से कमाए थे।

यह रकम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के एस्को खाते जमा होगी, जिसे इसी मकसद के लिए खोला गया है। सेबी ने रवींद्र बालू की पत्नी शुभांगी रवींद्र भारती और उनके इंस्टीट्यूट के निदेशकों- राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गोसावी को भी प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। ये लोग अब किसी भी रजिस्टर्ड मध्यस्थ से नहीं जुड़ सकेंगे।

क्या किया था यूट्यूबर ने?

रवींद्र भारती और उनकी पत्नी शुभांगी ने 2016 में रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड (RBEIPL) की नींव रखी थी। रवींद्र के दावे के मुताबिक- उनकी कंपनी लोगों को शेयर बाजार में निवेश का तरीका सिखाती थी। लेकिन, सेबी ने अपनी जांच में पाया कि रवींद्र की कंपनी



अपनी सलाह से लोगों को गुमराह करती थी। यह निवेशकों को 1,000 प्रतिशत तक के रिटर्न का लालच दे रही थी, जिसका कोई तुक ही नहीं था।

Sebi ने क्या कहा?

सेबी का कहना है कि पिछले कुछ समय से भारतीय शेयर बाजार जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है। छोटे निवेशकों का भी मार्केट पर भरोसा बढ़ा है। इसका फायदा उठाने के लिए बहुत

से लोग भारी रिटर्न दिलवाने का लालच देकर भोलेभाले निवेशकों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। निवेशकों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है।

सेबी ने कहा कि पारदर्शिता और स्पष्टीकरण बाजार के स्तंभ हैं। और इन दोनों के सहारे ही निवेशकों के पैसों और हितों की सुरक्षा की जा सकती है, तभी उनका बाजार पर भरोसा बना रहेगा।

आपकी EMI कम नहीं हो रही, कहीं जलवायु परिवर्तन तो नहीं इसकी वजह?

आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट- अप्रैल 2024 में कहा गया है कि वैश्विक औसत तापमान बढ़ रहा है। साथ ही एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स (EWE) में भी बढ़ोतरी हुई। इसका और ग्लोबल वार्मिंग का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव तेजी से सामने आ रहा है। इसके चलते केंद्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव करके जनता को राहत देने में दिक्कत हो रही है।

मुंबई। रिजर्व बैंक का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते लगातार होने वाले मौसम में असामान्य बदलाव मौद्रिक नीति के लिए चुनौती पैदा करते हैं। साथ ही, इससे आर्थिक विकास के मोर्चे पर जोखिम भी पैदा होता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट- अप्रैल 2024 में कहा गया है कि वैश्विक औसत तापमान बढ़ रहा है। साथ ही, एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स (EWE) में भी बढ़ोतरी हुई। इसका और ग्लोबल वार्मिंग का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव तेजी से सामने आ रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से मौसम के असामान्य झटके लगने का मिलसिला बढ़ गया है। इससे मौद्रिक नीति के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जब मौसम में कोई असामान्य बदलाव होता है, तो उसका बड़ा व्यापक असर पड़ता है। कृषि उत्पादन घट जाता है और सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ता है। इससे महंगाई बढ़ती है।

हर जगह एआई का जलवा, पर निवेश के मामले में कितनी भरोसेमंद इसकी सलाह?

AI ने कुछ ही समय में इंसानों के रहन-सहन से लेकर कामकाज का तरीका बदल दिया है। हर छोटे-बड़े काम में एआई का इस्तेमाल होने लगा है। वेयेरेबल टेक्नोलॉजी से डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड के दरम्यान फर्क खत्म होता नजर आ रहा है। ड्राइवरलेस कार हकीकत बनने की कगार पर है। अब सवाल उठता है कि क्या AI निवेश की सलाह देकर निवेशकों मालामाल कर सकता है?



नई दिल्ली। आज हर क्षेत्र में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का बोलबाला है। प्रोफेशनल लाइफ से लेकर रोजमर्रा के कामकाज में इसका इस्तेमाल हो रहा। यह ऑफिस में डेटा का हिसाब-किताब रख रहा, तो रेस्टोरेंट में खाना परोसने वाले रोबोट का दिमाग भी यही है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या AI निवेश की सलाह देने जैसा जटिल काम भी कर सकता है। आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं।

दुनिया बदल रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

AI ने कुछ ही समय में रहन-सहन से लेकर कामकाज का तरीका बदल दिया है। शॉपिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक में इसका दखल है। वेयेरेबल टेक्नोलॉजी से डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड के दरम्यान फर्क खत्म

होता नजर आ रहा है। ड्राइवरलेस कार हकीकत बनने की कगार पर है।

जिन क्षेत्रों में अभी AI नहीं है, उसमें भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कुछ समय में अपना दबदबा बना लेगी।

निवेश की सलाह भी दे पाएगा AI?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमूमन इंसानी काम की नकल करने की कोशिश करता है। कई मामलों में यह इंसानों से आगे है, तो कुछ में पीछे भी है। अगर निवेश की बात करें, तो यह काम बड़े पैमाने पर डेटा के इर्द-गिर्द ही घूमता है, जिसमें AI को महारत हासिल है।

यह वर्षों पुराने डेटा की तुलना करके बता सकता है कि किसी कंपनी के शेयर का रिटर्न देने का पैटर्न कैसा है और वह आगे चलकर कितना रिटर्न दे सकती है। लेकिन, क्या शेयर बाजार या किसी और सेक्टर में

निवेश के लिए इतना पर्याप्त है? जवाब जाहिर तौर पर है, नहीं।

AI की हद क्या है?

ब्रिटिश डेटा साइंटिस्ट क्लाइव हंबी ने साल 2006 में कहा था, 'डेटा नया तेल है।' लेकिन, आपको आँखों को शुद्ध करना पड़ता है। ठीक यही चीज डेटा के साथ भी है। अगर कोई इंसान या मशीन गलत डेटा उपलब्ध कराती है, तो उसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं।

2008 की आर्थिक मंदी के वक्त हम इसका नतीजा देख भी चुके हैं। उस वक्त एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यून होना था, कोलेटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन (CDO)। लेकिन, वह कर्ज से जुड़े जोखिम को ठीक से समझ नहीं पाया। लिहाजा, अमेरिका का पूरा हाउसिंग मार्केट की तबाह हो गया।

क्या AI से बेहतर हैं इंसान?

हर निवेश के साथ कई अन्य तरह के जोखिम भी जुड़े होते हैं। शेयर बाजार की ही मिसाल लीजिए, तो यह काफी संवेदनशील होता है। अगर किसी दूसरे में भी कोई संकट आता है, तो यह काफी तेजी से रिएक्ट करता है। इस बदलाव का आकलन इंसान तो कर सकता है, लेकिन AI जैसी टेक्नोलॉजी के लिए मुश्किल है।

यहां तक कि कई निवेशकों के सेंटिमेंट से बाजार में उतार-चढ़ाव आ जाता है। उसमें डेटा का कोई खास रोल नहीं होता। इस तरह की चीजों को भी भांपना भी एक मशीनी सिस्टम के लिए मुश्किल है। वहीं, इंसान इस तरह के मामलों में अपनी समझ से बेहतर फैसले ले सकता है।

इंसान-AI का तालमेल देगा बेहतर नतीजा

फिलहाल के लिए तो AI से निवेश लेना काफी जोखिम भरा होगा। बेशक, यह टेक्नोलॉजी इंसानों को निवेश से जुड़े बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। लेकिन, निवेश से जुड़ी भरोसेमंद सलाह नहीं दे सकती।

एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, 'टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। आप बस इंसानों को बेहतर टूल दीजिए, वे आपको शानदार नतीजे देंगे।' यही चीज AI के साथ भी है।

AI इंसान को डेटा दे सकता है। वहीं, इंसान बाजार की भावनाओं और व्यवहार को समझ कर निवेश से जुड़े बेहतर फैसले ले सकता है। मतलब कि इंसान का अभी के लिए AI से सिर्फ डेटा लेना फायदेमंद रहेगा। निवेश के लिए पूरी तरह से AI की सलाह काफी जोखिम भरी साबित हो सकती है।

इस वित्तीय संस्थान में एफडी पर मिलेगा बाकी की तुलना में ज्यादा फायदा, जानें अब कितना मिलेगा ब्याज



कई लोग बिना जोखिम के निवेश करना पसंद करते हैं। ऐसे में फिक्सड डिपॉजिट काफी अच्छा ऑप्शन है। आज एफडी स्कीम में निवेश करने वालों के लिए गुड न्यूज है। बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) ने एफडी की दरों में 60 आधार अंक (बीपीएस) की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरें 3 अप्रैल 2024 से लागू हो गई हैं।

नई दिल्ली। बिना रिस्क के निवेश करने के लिए एफडी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज एफडी में निवेश करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। आज बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv) की सहायक कंपनी बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) ने एफडी की दरों में 60 आधार अंक (बीपीएस) तक की बढ़ोतरी का एलान किया है।

बता दें कि बजाज फाइनेंस एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। बैंक की नई एफडी रेट 3 अप्रैल 2024 से लागू हो गई है।

कितने टैन्डोर पर बढ़ा कितनी बीपीएस

कंपनी ने सीनियर सिटीजन के लिए 25-35 महीने के टैन्डोर वाले एफडी रेट में 60 बीपीएस की बढ़ोतरी की है। वहीं, 18-24 महीने के टैन्डोर वाले एफडी में 40 बीपीएस प्वाइंट की वृद्धि हुई है। बजाज फाइनेंस ने आम जनता के एफडी रेट में भी बढ़ोतरी की है। 25-35 महीने के टैन्डोर वाले एफडी पर 45 बीपीएस बढ़ाया गया है, जबकि 8 और 22 महीने की टैन्डोर वाले एफडी में 40 आधार अंक और 30 और 33 महीने की अवधि में 35 आधार अंक तक की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने नए एफडी रेट को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया है।

आगर सिनियर सिटिजन 42 महीने के टैन्डोर वाले एफडी की डिजिटल बुकिंग करते हैं तो उन्हें 8.85 प्रतिशत तक की एफडी दरों का लाभ उठा सकते हैं। वहीं आम जनता को इस एफडी पर 8.6 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।

बजाज फाइनेंस ने कहा कि कंपनी 31 मार्च, 2024 तक 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की डिपॉजिट बुक के साथ देश की सबसे बड़ी जमा लेने वाली एनबीएफसी के रूप में उभरी है।

सोने का रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी, 350 रुपये बढ़कर नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा भाव



2024 में सोने के दाम में अब तक 7700 रुपये का उछाल आ चुका है। पिछले कारोबारी सत्र में यह 71350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। विदेशी बाजारों में सोने की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में निवेशक इसे बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। सोमवार को गोल्ड में 350 रुपये का उछाल आया।

नई दिल्ली। सोने (Gold) की कीमतों में लगातार उछाल दिख रहा है। सोमवार को गोल्ड में 350 रुपये का उछाल आया और यह 71,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक, वैश्विक बाजार में डिमांड बढ़ने से पीली धातु का दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा है।

2024 में सोने की शानदार चमक

इस साल यानी 2024 में सोने के दाम में अब तक 7,700 रुपये का उछाल आ चुका है। पिछले कारोबारी सत्र में यह 71,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। HDFC सिक्योरिटीज ने क्मोडिटीज के सीनियर एनालिस्ट सोमिल गांधी का कहना है कि विदेशी बाजारों में सोने की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में निवेशक इसे बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं।

चांदी का क्या हाल है?

चांदी में भी सोने की तरह 800 रुपये का तेज उछाल आया है। राष्ट्रीय राजधानी में एक किलो चांदी का भाव फिलहाल 84,000 रुपये तक पहुंच गया है। पिछले ट्रेड में यह 83,200 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, COMEX पर सोना हाजिर 2,336 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 7 अमेरिकी डॉलर अधिक है।

अमेरिकी जॉब रिपोर्ट नजरअंदाज

अमेरिका में बेहतर जॉब रिपोर्ट आई है, लेकिन कारोबारियों ने उस ध्यान नहीं दिया। उनका फोकस सरफा बाजार पर ही रहा, जिसमें पिछले काफी वक्त तेजी दिख रही है। यही वजह है कि सोने का भाव नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है।

क्यों बढ़ रहा सोने का भाव?

दरअसल, भारत समेत दुनियाभर के केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं, लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ब्याज दरों में बदलाव की आशंका के बीच निवेशक भी सोने को ज्यादा तवज्जी दे रहे, जिसे सुरक्षित निवेश माना जाता है।

हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि अगर चीजें सामान्य रहें, तो निकट भविष्य में सोने के भाव में मामूली गिरावट आएगी। और यह 69,500 रुपये के स्तर आ सकता है।

बंधन बैंक के CEO के इस्तीफे की खबर ने निवेशकों को रुलाया, शेयरों में आई बड़ी गिरावट

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जेफरीज ने बंधन बैंक के शेयर का टारगेट प्राइस 40 प्रतिशत तक घटा दिया। उसने बैंक की रेटिंग को भी Buy से डाउनग्रेड करके अंडरपरफॉर्म कैटेगरी में डाल दिया। पहले उसने बंधन बैंक के लिए 290 रुपये का टारगेट प्राइस रखा था लेकिन अब इसे घटाकर 170 रुपये कर दिया है। यह सब बंधन बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष के इस्तीफे की खबर के बाद हुआ है।

नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक (Bandhan Bank) के शेयरों में सोंगवार को बड़ी गिरावट आई। दरअसल, Bandhan Bank के फाउंडर और सीईओ चंद्रशेखर घोष ने इस्तीफा दे दिया है। इससे निवेशकों को लगा कि बैंक सही प्रदर्शन नहीं कर रहा। लिहाजा, उन्होंने ज़ब्त बिकवाली की। शुरुआती कारोबार में यह 9 फीसदी टूट गया था। लेकिन, बाद में थोड़ी रिकवरी हुई और यह 6.11 प्रतिशत गिरकर 185.10 रुपये पर बंद हुआ।

9 जुलाई को रिटायर होने वाले थे सीईओ चंद्रशेखर घोष (Chandra Shekhar Ghosh) 9 जुलाई 2024 को रिटायर होने वाले थे। लेकिन, उन्होंने उससे पहले ही बोर्ड को अपना इस्तीफा भेज दिया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जेफरीज ने बंधन बैंक के शेयर का टारगेट प्राइस 40 प्रतिशत तक घटा दिया। उसने बैंक की रेटिंग को भी Buy से डाउनग्रेड करके अंडरपरफॉर्म कैटेगरी में डाल दिया।

